बढ़े हुए मुनाफे पर कटौती के माध्यम से अध्याय

परिपत्र संख्या 37/2016 [एफ.सं.279/MISC./140/2015/ITJ], दिनांक 2-11-2016

आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") का अध्याय VI-A, कुछ आय के संबंध में कटौती का प्रावधान करता है। किसी व्यावसायिक गतिविधि के लाभ और लाभ की गणना करते समय, मूल्यांकन अधिकारी कुछ अस्वीकृतियाँ कर सकता है, जैसे कि अधिनियम की धारा 32, 40(a)(ia), 40A(3), 43B आदि से संबंधित अस्वीकृतियाँ। कभी-कभी दावा किए गए विशिष्ट व्यय से भी अस्वीकृति की जा सकती है। ऐसी अस्वीकृतियों का प्रभाव लाभ में वृद्धि है। इस बारे में संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या ऐसे उच्च लाभ अध्याय VI-A के तहत उच्च लाभ-लिंक्ड कटौती के लिए दावे का कारण बनेंगे।

2. बढ़े हुए लाभ पर उच्च कटौती के दावे का मुद्दा विवादास्पद रहा है। हालाँकि, न्यायालयों ने आम तौर पर माना है कि यदि अस्वीकृत व्यय उस व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित है जिसके विरुद्ध अध्याय VI-A कटौती का दावा किया गया है, तो कटौती को बढ़े हुए लाभ पर अनुमति दी जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण को बनाए रखने वाले कुछ उदाहरणात्मक मामले इस प्रकार हैं:

(i) यदि आवास परियोजना के विकास के उद्देश्य से करदाता द्वारा किया गया व्यय कानून के तहत टीडीएस की कटौती न किए जाने के कारण स्वीकार्य नहीं था, तो ऐसी अस्वीकृति अंततः आवास परियोजना के विकास के व्यवसाय से करदाता के लाभ को बढ़ाएगी। अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) के तहत अस्वीकृति को समायोजित करने के बाद करदाता का अंतिम लाभ अधिनियम की धारा 80-आईबी के तहत कटौती के लिए योग्य होगा। न्यायालयों ने निम्नलिखित मामलों में यह दृष्टिकोण अपनाया:

आयकर अधिकारी - वार्ड 5(1) बनाम केवल कंस्ट्रक्शन, कर अपील संख्या 443 वर्ष 2012, 10 दिसंबर, 2012, गुजरात उच्च न्यायालय।

आयकर आयुक्त-IV, नागपुर बनाम सुनील विश्वम्भरनाथ तिवारी, आयकर अपील संख्या 2 वर्ष 2011, 11 सितंबर, 2015, बॉम्बे उच्च न्यायालय।

(ii) यदि अधिनियम की धारा 40ए(3) के तहत कटौती की अनुमति नहीं है, तो उसे उपक्रम के मुनाफे में जोड़ना होगा, जिस पर करदाता अधिनियम की धारा 80झख के तहत कटौती के लिए हकदार होगा। न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में यह दृष्टिकोण अपनाया:

प्रिंसिपल सीआईटी, कानपुर बनाम सूर्या मर्चेंट्स लिमिटेड आईटी अपील संख्या 248/2015, 03 मई, 2016, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

उपरोक्त विचार अंतिम हो गए हैं क्योंकि बॉम्बे, गुजरात और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के इन निर्णयों को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, बोर्ड ने यह स्थापित स्थिति स्वीकार कर ली है कि अधिनियम की धारा 32, 40(ए)(आइए), 40ए(3), 43बी, आदि के तहत की गई अस्वीकृतियां और अन्य विशिष्ट अस्वीकृतियां, जो उस व्यवसायिक गतिविधि से संबंधित हैं जिसके विरुद्ध अध्याय VI-ए कटौती का दावा किया गया है, के परिणामस्वरूप पात्र व्यवसाय के मुनाफे में वृद्धि होती है, और अस्वीकृति द्वारा इस प्रकार बढ़ाए गए मुनाफे पर अध्याय VI-ए के तहत कटौती स्वीकार्य है।

4. तदनुसार, अब से, विभाग के अधिकारियों द्वारा इस आधार पर अपील दायर नहीं की जा सकती है और न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में पहले से दायर अपीलों को वापस लिया जा सकता है/उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। उपरोक्त सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।